नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 051
दि. 23.11.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

न्यूक्लियर सेक्टर से लेकर शिक्षा सुधार तक: संसद के शीतकालीन सत्र में बड़े बदलावों का खाका तैयार, कई ऐतिहासिक विधेयक पेश होने की तैयारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र इस बार कई अहम बदलावों और निर्णायक कानूनों का गवाह बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने आगामी सत्र के लिए दस बड़े विधेयकों की सूची तैयार कर ली है, जिनमें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का कायाकल्प करने वाला एटॉमिक एनर्जी बिल से लेकर पूरे उच्च शिक्षा ढांचे को बदल देने वाला हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल तक शामिल हैं। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा और इन उन्नीस दिनों में कुल पंद्रह बैठकों के माध्यम से सरकार देश के सामाजिक, आर्थिक और विधिक ढांचे में व्यापक सुधारों का आधार तैयार करना चाहती है।

इस बार सबसे अधिक चर्चा एटॉमिक एनर्जी बिल को लेकर है, जो भारत में न्यूक्लियर पावर सेक्टर के दरवाजे निजी कंपनियों के लिए खोलने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन केवल सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियों जैसे कि एनपीसीआईएल के माध्यम से ही संभव था, लेकिन प्रस्तावित बदलावों के बाद न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी न्यूक्लियर प्लांट लगाने और ऊर्जा उत्पादन में भागीदारी कर सकेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह न केवल निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता को तेज़ी से बढ़ाने का रास्ता भी खोलेगा।

इसी तरह उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ा ढांचा परिवर्तन होने जा रहा है। सरकार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल पेश करने वाली है, जिसके लागू हो जाने के बाद यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसी संस्थाएँ अस्तित्व में नहीं रहेंगी। उनकी जगह एक एकीकृत आयोग बनेगा, जो देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देने का प्रयास करेगा। यह माना जा रहा है कि इससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, साथ ही प्रशासनिक संरचना सरल और पारदर्शी बनेगी।

इस सत्र में सड़कों और राजमार्गों से जुड़े मामलों पर भी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। नेशनल हाईवे संशोधन बिल के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाने की योजना है। केंद्र सरकार का मानना है कि हाईवे प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी का सबसे बड़ा कारण भूमि अधिग्रहण से जुड़ी बाधाएँ हैं, और यह नया विधेयक उन समस्याओं को काफी हद तक हल कर सकता है।

कॉरपोरेट जगत के लिए भी यह

सत्र महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 और एलएलपी अधिनियम 2008 में बड़े बदलावों वाले नए कॉरपोरेट लॉ (अमेंडमेंट) बिल को भी पेश करने की तैयारी है। सरकार का उद्देश्य व्यापार करने की प्रक्रिया को अधिक सरल और अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से मुक्त करना है। इसके साथ ही सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल भी आने वाला है, जो सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट को एक ही कानून में सम्मिलित कर देगा। इससे देश के शेयर बाजार और पूंजी बाजार से जुड़े सभी कानून एक ही छतरी के नीचे आ जाएंगे और निवेशकों तथा कंपनियों दोनों के लिए व्यवस्था सरल हो जाएगी।

इस सत्र में संविधान के 131वें संशोधन विधेयक को भी पेश किया जाएगा, जिसके माध्यम से चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इससे केंद्र सरकार को चंडीगढ़ के लिए सीधे विनियम बनाने का अधिकार प्राप्त होगा, जिन्हें कानून का दर्जा मिलेगा। यह बदलाव केंद्रशासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था को और स्पष्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

व्यापार से लेकर व्यक्तिगत मामलों तक, विवादों के समाधान को तेज़ और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार एक और महत्वपूर्ण बिल—ऑर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल—भी लेकर आ रही है। इस बिल का उद्देश्य मध्यस्थता के फैसलों को चुनौती देने की प्रक्रिया को सरल बनाना और व्यवसायिक विवादों का वर्षों तक अदालतों में लंबित रहना रोकना है, ताकि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक विवाद समाधान केंद्रों की श्रेणी में अपनी स्थिति मजबूत कर सके।

सत्र का कार्यक्रम पहले से ही व्यस्त और चुनौतीपूर्ण है। इससे पहले जुलाई से अगस्त तक चले मानसून सत्र में लगातार राजनीतिक टकराव और विपक्ष के विरोध के कारण कई दिन बेकार चले गए थे। लोकसभा में 120 घंटे की चर्चा के बदले केवल 37 घंटे ही काम हो पाया था। राज्यसभा की स्थिति भी इससे अलग नहीं थी। ऐसे में सरकार इस बार अधिक उत्पादक सत्र की उम्मीद में है, ताकि देश के लिए तैयार किए जा रहे इन महत्वपूर्ण विधायी सुधारों को लंबी अवधि में क्रियान्वयन का मजबूत आधार मिल सके। इस शीतकालीन सत्र को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि जिन बिलों को प्रस्तुत किया जाना है वे देश के ऊर्जा, शिक्षा, आधारभूत ढांचे, कॉरपोरेट गवर्नेंस और संवैधानिक व्यवस्था के बड़े हिस्से को सीधे प्रभावित करेंगे। आने वाले वर्षों में भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा, उसकी तस्वीर इन विधेयकों से काफी हद तक स्पष्ट होने जा रही है। सरकार और विपक्ष दोनों की रणनीति इस सत्र में अधिक पारदर्शी और व्यापक बहस की ओर हो सकती है, क्योंकि ये बदलाव केवल कानूनी संशोधन नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी संरचना निर्मित करने का प्रयास हैं।

तेलंगाना में माओवादी उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता, 37 हथियारबंद नक्सली ने किया आत्मसमर्पण

(जीएनएस)। हैदराबाद। तेलंगाना में नक्सल उन्मूलन अभियान को शनिवार को बड़ी सफलता मिली, जब 37 माओवादी हथियारबंदों ने पुलिस महानिदेशक शिवधर रेड्डी के सामने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। सरेंडर करने वालों में संगठन के शीर्ष नेता आज़ाद, नारायण और एर्रालू सहित 25 महिलाएं भी शामिल हैं। यह घटना राज्य सरकार की नीतियों और लगातार पुलिस दबाव के बीच हुई, जो माओवादियों के खिलाफ व्यापक अभियान का हिस्सा है। सरेंडर करने वाले माओवादियों ने पुलिस को एके-47, एसएलआर, जी3 राइफल, 303 राइफल और भारी मात्रा में कारतूस समेत कई हथियार सौंपे। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आह्वान और राज्य सरकार की पुनर्वास योजनाओं के प्रभाव ने माओवादी नेताओं को हिंसा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी आत्मसमर्पण करने वालों को इनाम राशि, पुनर्वास सहायता और सुरक्षित भविष्य का आश्वासन दिया।

सरेंडर करने वाले 37 माओवादी नेताओं पर कुल मिलाकर लगभग 1.41 करोड़

रुपये का इनाम घोषित था। अब यह राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। सरेंडर करने वालों में तीन राज्य समिति सदस्य—आज़ाद, नारायण और एर्रालू—भी शामिल हैं, जो संगठन के शीर्ष स्तर के रणनीतिक नेता माने जाते हैं।

डीजीपी ने बताया कि राज्य में अभी भी 59 माओवादी सक्रिय हैं, जिनमें सेंट्रल कमेटी के कई प्रमुख नाम शामिल हैं। उन्होंने सभी को पुनः आत्मसमर्पण करने और हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का आग्रह किया। सरेंडर करने वाले माओवादी नेता आज़ाद ने प्रेसवार्ता के दौरान अपने साथियों से भी यही अपील की और इसे समाज के प्रति जिम्मेदार कदम बताया।

विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के दिनों में हुए बड़े एनकाउंटर और पुलिस की निरंतर सघन निगरानी का असर माओवादी संगठन पर पड़ा है। राज्य सरकार और पुलिस द्वारा जारी पुनर्वास योजनाओं ने हथियारबंदों को आत्मसमर्पण की राह अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इसमें न केवल आर्थिक सहायता शामिल है, बल्कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक पुनर्वास की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे माओवादी हिंसा के खिलाफ दीर्घकालिक स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

सरेंडर अभियान को राज्य में माओवादी उन्मूलन के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के अनुसार, इस कदम से स्थानीय समुदायों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। यह घटना राज्य और केंद्र सरकार के समन्वित प्रयासों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य माओवादी हिंसा को जड़ से खत्म करना और प्रभावित क्षेत्रों को स्थायी शांति और विकास की ओर ले जाना है।

नाइजर राज्य में सेंट मैरी स्कूल से 227 छात्र और शिक्षक अगवा, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

(जीएनएस)। अबुजा। नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी नाइजर राज्य में शुक्रवार को एक भयावह घटना ने देश को हिला दिया। सशस्त्र बंदूकधारी हमलावरों ने सेंट मैरी कैथोलिक स्कूल पर अचानक हमला किया और कम से कम 227 छात्रों और शिक्षकों को जबरन उठाकर जंगल की ओर ले गए। क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया (सीएएन) ने इस गंभीर अपहरण की पुष्टि की है। यह घटना 2014 के कुख्यात चिबोक अपहरण की याद ताजा कर रही है, जब बोको हराम आतंकियों ने 276 स्कूली लड़कियों को अगवा कर लिया था।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने स्कूल परिसर में प्रवेश कर बच्चों और शिक्षकों को घेर लिया और उन्हें हथियार के बल पर स्कूल से बाहर निकालकर जंगल की ओर ले गए। नाइजर राज्य प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने अपहरण की पुष्टि की है, हालांकि अब तक सटीक संख्या पर पूरी तरह से जानकारी नहीं मिली है। सुरक्षा बलों ने अपहृत छात्रों और शिक्षकों को ढूँढने के लिए आस-पास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

राज्य सरकार का कहना है कि स्कूल ने पहले जारी किए गए निर्देशों की अवहेलना

की, जिसमें बोर्डिंग स्कूलों को सुरक्षा खतरे के चलते अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश था। यह घटना इस सप्ताह में शैक्षणिक संस्थानों पर हुए कई हमलों में से एक है, जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

इससे पहले सोमवार को केबी राज्य के एक बोर्डिंग स्कूल से 25 लड़कियों का अपहरण किया गया था, वहीं क्वारा राज्य में एक चर्च पर हमला हुआ, जिसमें 38 लोग अगवा किए गए। इन घटनाओं ने नाइजर राज्य और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा की संवेदनशील स्थिति को उजागर किया है।

नाइजीरिया में सुरक्षा की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में बोको हराम और आईएस जैसे आतंकवादी समूह सक्रिय हैं, जबकि उत्तर-पश्चिम में फिरौती के लिए अपहरण करने वाले गिरोह काम कर रहे हैं। मध्य क्षेत्र में किसानों और चरवाहों के बीच हिंसा बढ़ रही है। इन सभी परिस्थितियों ने देश की सुरक्षा को और जटिल बना दिया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम की निंदा हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नाइजीरिया में ईसाइयों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी। नाइजीरिया सरकार ने इसे 'गलतफहमी' बताया और स्पष्ट किया कि देश की समस्याएँ धार्मिक नहीं, बल्कि सुरक्षा से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर हमलों की बढ़ती प्रवृत्ति नाइजर राज्य में व्यापक सुरक्षा खतरे की चेतावनी देती है। बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभावी उपाय, स्थानीय सुरक्षा बलों की मजबूत उपस्थिति और समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। इस अपहरण ने नाइजीरिया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या देश में शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, और कब तक यह भयावह स्थिति समाप्त होगी। अभी तक अपहृत छात्रों और शिक्षकों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा बलों का दावा है कि वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही अपहृत सभी लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जाएगा।

देश के प्रमुख एयरपोर्ट होंगे एंटी-ड्रोन सिस्टम की निगरानी में, सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी तेज

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देशभर के प्रमुख हवाई अड्डों पर ड्रोन हमलों की बढ़ती आशंकाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाने का फैसला किया है। हाल ही में हुई जांचों में और वैश्विक सुरक्षा माहौल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। दिल्ली कार धमाके की जांच में भी संकेत मिले थे कि आतंकवादी संगठन ड्रोन हमलों की साजिश रच रहे थे, जिससे सुरक्षा को लेकर खतरे की घंटी बज गई। सूत्रों के अनुसार, यह पहली बार है जब भारत के सिविल एयरपोर्ट पर इस तरह की हाई-टेक सुरक्षा व्यवस्था लागू होने जा रही है। गृह मंत्रालय इस परियोजना की निगरानी कर रहा है, जबकि BCAS ने DGCA, CISF और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष कमेटी बनाई है, जो तकनीकी मानकों से लेकर सिस्टम की स्थापना तक पूरी प्रक्रिया पर काम कर रही है। इस कमेटी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में लगाए जाने वाले सिस्टम विश्वसनीय और प्रभावी हों। अधिकारियों ने बताया कि एंटी-ड्रोन सिस्टम के स्पेसिफिकेशन पर अंतिम रूप दिया जा रहा है और मंजूरी मिलने के तुरंत बाद खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। परियोजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर और जम्मू जैसे उच्च जोखिम वाले हवाई अड्डों को कवर किया जाएगा। इसके बाद धीरे-धीरे अन्य प्रमुख एयरपोर्टों को भी इस सुरक्षा कवच से लैस किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि दुनिया के अन्य एयरपोर्ट पर सफल मॉडलों का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि भारत में लगाए जाने वाले सिस्टम को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाया जा सके। ड्रोन तकनीक के तेजी से बढ़ते खतरे को देखते हुए यह कदम हवाई अड्डों की सुरक्षा को अपग्रेड करने के लिए जरूरी है। अधिकारी मानते हैं कि आने वाले समय में यह व्यवस्था न केवल नागरिक सुरक्षा बढ़ाएगी बल्कि आतंकवाद और अवैध गतिविधियों की रोकथाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। अब यात्रियों, एयरलाइंस और कर्मचारी सुरक्षा में और अधिक आश्वस्त महसूस कर सकेंगे, जबकि किसी भी संभावित ड्रोन खतरे का सामना पहले से तैयार एंटी-ड्रोन सिस्टम कर सकेगा।

बिहार–नेपाल सीमा पर UAE नागरिक समेत दो संदिग्ध गिरफ्तार अवैध पारगमन का मामला सामने

(जीएनएस)। पूर्वी चंपारण। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में भारत–नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के एक नागरिक समेत दो लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों व्यक्ति ग्रामीण मार्ग से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उनके संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए सीमा सुरक्षा बल (SSB) और नेपाल सशस्त्र पुलिस की संयुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई की।

गिरफ्तार व्यक्तियों में एक की पहचान सीतामढ़ी निवासी अनवर के रूप में हुई, जबकि दूसरे व्यक्ति यूएई के निवासी सलेम अब्दुल्ला खलफान अल शम्सी (34) हैं। अल शम्सी के पास वैध पासपोर्ट था, लेकिन उसकी यात्रा को लेकर कई सवाल उठ गए, क्योंकि पासपोर्ट पर भारत से निकासी का कोई आधिकारिक 'डिपार्चर स्टाम्प' नहीं था।

दोनों संदिग्धों को नो-मैन्स लैंड के पिलर संख्या 389/9 के पास सहदेवा गांव से बलिरामपुर की ओर जाते समय रोका गया। पूछताछ में पता चला कि अल शम्सी 8 मार्च 2025 को टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, जो 29 अगस्त 2025 तक वैध था। उसके पास मुंबई एफआरआरओ द्वारा जारी वीजा विस्तार की पावती भी थी। पासपोर्ट में भारत से निकासी का कोई रिकॉर्ड न होने के कारण सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों को तुरंत इमिग्रेशन ब्यूरो के हवाले कर दिया।

पूछताछ में अल शम्सी ने बताया कि वह अबू धाबी के अल ऐन का निवासी है और भारत में टूरिज्म और बिजनेस अवसरों की तलाश में आया था। उसने यह भी खुलासा किया कि वह रक्सौल के एक होटल में जम्मू-कश्मीर के राजौरी निवासी हक नवाज़ के साथ ठहरा था, जो अबू धाबी स्थित उसके कैफे में काम करता है। अनवर ने अल शम्सी को नेपाल के वीरगंज तक पहुँचाने का आश्वासन दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि अनवर के पास भारत और नेपाल दोनों के संदिग्ध दस्तावेज थे और वह अवैध तरीके से लोगों को सीमा पार कराने में सक्रिय था। हक नवाज़ का नाम भी मामले में जुड़ा है। गिरफ्तारी की जानकारी मिलने पर वह नेपाल की बलिरामपुर बीसीपी पहुँचा। सुरक्षा एजेंसियां तीनों संदिग्धों से गहन पूछताछ कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह मामला केवल अवैध पारगमन का था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। अधिकारियों ने बताया कि सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस गिरफ्तारी से भारत–नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी करने और अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद मिलने की संभावना है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

जानलेवा बनता शिक्षकों का संवेदनहीन रवैया

यह खबर विचलित करने वाली है कि दिल्ली में एक सोलह वर्षीय छात्र और जयपुर में एक नौ साल की छात्रा ने स्कूल की असहज स्थितियों के चलते आत्महत्या कर ली है। निस्संदेह, ये आत्महत्या की घटनाएं एक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर करती हैं। भारत के स्कूल, जिनका उद्देश्य बच्चों का पालन-पोषण और सुरक्षा करना है, तेज़ी से ऐसे स्थानों में बदल रहे हैं जहां क्रूरता, उपेक्षा और अनियंत्रित अधिकार बच्चों के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। ये त्रासदियां कोई असामान्य बात नहीं हैं; ये एक असफल व्यवस्था के लक्षण हैं। तीसरी भयावह घटना महाराष्ट्र के वसई की है जहां एक तेरह साल की छात्रा को किसी कारणवश स्कूल देर से पहुंचने पर शिक्षक ने अमानवीय सजा दी। छात्रा को स्कूल बैग के साथ सौ उठक-बैठक लगाने को बाध्य किया गया। यह तथ्य नजरअंदाज करते हुए कि वह एनीमिया से पीड़ित है। छात्रा कुछ देर के बाद बेहोश हो गई और कालांतर में उसकी मौत हो गई। निस्संदेह, एक छात्र व एक छात्रा की आत्महत्या और महाराष्ट्र के वसई में छात्रा की उठक-बैठक लगाने से हुई मौत एक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर करती है। स्कूल जिनका उद्देश्य छात्र-छात्राओं को पालन-पोषण और सुरक्षा करना था, वे बच्चों के जीवन पर संकट की वजह बन रहे हैं। वहां शिक्षकों की संवेदनहीनता, उपेक्षा और सख्त व्यवहार कई बच्चों का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। ये त्रासदियां असामान्य बात नहीं, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की असफलता की कहानी कहती है। दिल्ली में, मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाने वाले किशोर ने अपने शिक्षकों के हाथों अपमान का हृदय विदारक वर्णन करते हुए एक पत्र छोड़ा है। उसके माता-पिता ने छात्र के उत्पीड़न का आरोप शिक्षकों पर लगाया है। उनका आरोप है कि उसे छोटी-छोटी बात पर डांटा गया, निष्कासन की धमकी दी गई और सहपाठियों के सामने मजाक उड़ाया गया।

आत्महत्या करने वाले छात्र के अभिभावकों द्वारा प्राथमिकी में बताया गया कि छात्र ने मन में आने वाले आत्महत्या के विचार से काउंसलर को अवगत कराया था। लेकिन शिक्षकों ने न तो माता-पिता को सूचित किया और न ही उसे इस दिशा में सोचने से रोकने के लिये कोई सलाह दी गई। निश्चित रूप से जब कोई छात्र अपनी किसी गंभीर समस्या का जिक्र करता है तो ऐसे में उदासीनता हिंसा का एक रूप ही कही जाएगी। वहीं दूसरी ओर जयपुर में नौ वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में सीबीएसई की जांच में संस्थागत उदासीनता का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि पिछले 18 महीने से छात्रा अन्य छात्राओं द्वारा परेशान की जा रही थी। जिस दिन छात्रा ने आत्महत्या की, उस दिन वह अपनी सहपाठियों द्वारा लिखी गई, अश्लील सामग्री से स्पष्ट रूप से व्यथित होकर 45 मिनट में पांच बार अपनी शिक्षिका के पास शिकायत लेकर गई थी। शिक्षिका ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया और उलटा उसे ही डांटा। निश्चित रूप से शिक्षिका ने छात्रा की देखभाल के अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया। कमोबेश वसई की घटना भी शिक्षक की घोर संवेदनहीनता को ही दर्शाती है, जिसने एनीमिया से पीड़ित छात्रा से बैग के साथ सौ उठक-बैठक लगवाई। हालांकि, शिक्षक को गैर-इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन छात्रा का जीवन वापस नहीं लौटाया जा सकता। निश्चित रूप से तीन राज्यों में तीन विद्यार्थियों की मौत हमारी संवेदनहीन व्यवस्था को ही दर्शाती है। दरअसल, आज स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिये कारगर कानून के अलावा भावनात्मक संकट की रिपोर्टिंग अनिवार्य करने की जरूरत है। स्कूलों में प्रशिक्षित परामर्शदाता होने चाहिए। साथ ही किसी बच्चे के भावनात्मक व शारीरिक शोषण रोकने के लिये सख्त दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ताकि भविष्य में किसी संभावना का यूं दुखद अंत न हो। इक्कीसवीं सदी के बच्चे नये दौर में नये सपनों की उड़ान लिए हुए हैं, वे अपनी अस्मिता व सम्मान के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। एकाकी परिवार में वे मां-बाप के लाड-प्यार से पलते हैं। जब भी उनके अहम को ठेस लगती है वे असहज हो जाते हैं। ऐसे में शिक्षकों का सतर्क व संवेदनशील व्यवहार जरूरी है।

नई श्रम संहिताएँ सुधार की दिशा में बड़ा कदम, मगर इनकी सफलता सही क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी

> देखा जाये तो यह सुधार भारत के श्रम परिदृश्य को भविष्य-तैयार और अधिक न्यायसंगत बना सकता है। लेकिन यदि इनका क्रियान्वयन कमजोर रहा, तो यह वही कहानी दोहराएगा— यानि बड़े वादों के नीचे दबा हुआ श्रमिक का वास्तविक संघर्ष।

21 नवंबर 2025 से लागू हुई चार नई श्रम संहिताएँ— वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता, सिर्फ़ कानूनों का पुनर्गठन भर नहीं हैं, बल्कि यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पहचानने वाला ढाँचा है। सरकार इसे आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा श्रम सुधार बता रही है, जबकि ट्रेड यूनियनें इसे श्रमिक-अधिकारों पर तलवार मान रही हैं। परंतु सच यह है कि इन संहिताओं के भीतर अवसर और जोखिम दोनों छिपे हुए हैं और वास्तविक फर्क इनकी जमीनी क्रियान्वयन-क्षमता ही तय करेगी। सबसे पहले, इन संहिताओं का सबसे सकारात्मक तत्व यह है कि वे भारत की श्रम व्यवस्था को एकीकृत, सरल और दस्तावेज़ी बनाती हैं। नियुक्ति पत्र अनिवार्य होना, न्यूनतम वेतन का सार्वभौमिक अधिकार, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना तथा 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण, ये ऐसे कदम हैं जिन्हें लंबे समय से औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने की प्रतीक्षा कर रहे करोड़ों कर्मचारियों को एक नई पहचान देते हैं। यह कानूनी ढांचा न केवल श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ा सकता है, बल्कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भी मजबूत कर सकता है।

लेकिन, यह तस्वीर का सिर्फ़ एक भाग है। दूसरी ओर, इन संहिताओं में नियोक्ता-पक्षीय प्रावधान भी हैं— विशेषकर छंटनी की मंजूरी सीमा को 100 से बढ़ाकर 300

कर्मचारियों तक ले जाना। इसे "उद्योग-अनुकूल लचीलेपन" के नाम पर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसका अर्थ है कि हज़ारों इकाइयाँ अब बिना सरकारी अनुमति के बड़े पैमाने पर छंटनी कर सकेंगी। यह संभावना वास्तविक चिंता पैदा करती है कि कहीं श्रम-बाज़ार में स्थायित्व के बदले अस्थिरता न बढ़ जाए। इसी प्रकार, कार्य-घंटों में बढ़ोतरी और औद्योगिक विवादों में उच्चतर अनुपालन-सीमा श्रमिकों को दबाव में डाल सकती है।

नई संहिताएँ महिलाओं के लिए सुरक्षित रात्रिकालीन कार्य की अनुमति देती हैं। यानि यह एक सराहनीय बदलाव है। पर यह तभी प्रभावी होगा जब सुरक्षा-प्रबंध, परिवहन और निगरानी-तंत्र उतनी ही गंभीरता से लागू हो। अन्यथा, "सहमति आधारित रात्रि-कार्य" कागज़ पर सशक्तिकरण और ज़मीनी स्तर पर अतिरिक्त जोखिम बनकर रह सकता है। समान वेतन और समान अवसर का अधिकार तभी सार्थक होगा जब निजी व सरकारी दोनों क्षेत्र व्यावहारिक उपायों में निवेश करें।

सामाजिक सुरक्षा संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों को औपचारिक ढाँचे से जोड़ना ऐतिहासिक है— किन्तु इसका परिणाम पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि योगदान का मॉडल कैसा बनेगा, नियमन कितना पारदर्शी होगा और अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय होगी। यदि सामाजिक सुरक्षा कोष के स्रोत स्पष्ट न हों, तो यह कदम एक बार फिर प्रतीकात्मकता में बदलने का जोखिम रखता है।

औद्योगिक संबंध संहिता में त्वरित विवाद-निपटान, रिस्किलिंग फंड और निश्चित अवधि के रोजगार को औपचारिक मान्यता जैसे सुधार उद्योगों के लिए सकारात्मक माने जा सकते हैं। परन्तु इन सबके बीच यह भी ज़रूरी है कि श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, और "संवाद-तंत्र" महज औपचारिक न होकर वास्तविक भागीदारी पर आधारित हो।

मुद्दा यह नहीं कि संहिताएँ अच्छी हैं या बुरी। मुद्दा यह है कि क्या भारत उस संस्थागत क्षमता, नियामकीय मजबूती और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ इस परिवर्तन को जमीन पर उतारने को तैयार है। पुराने श्रम कानूनों की सबसे बड़ी विफलता उनकी जटिलता नहीं, बल्कि उनका कमजोर क्रियान्वयन था। यदि नई संहिताएँ भी इसी राह पर चलीं, तो सुधार सिर्फ़ स्लोगन बनकर रह जाएगा।

बहरहाल, इन संहिताओं का वादा एक ऐसे श्रम बाज़ार का है जो पारदर्शी भी हो, उद्योग-अनुकूल भी और श्रमिकों के लिये सुरक्षात्मक भी। पर यह संतुलन केवल नियमों से नहीं, बल्कि विश्वसनीय निगरानी, निष्पक्ष प्रवर्तन और श्रमिकों के हितों को केंद्र में रखकर ही संभव होगा। यदि सरकार इस दिशा में सुसंगत और संवेदनशील कदम उठाती है, तो यह सुधार भारत के श्रम परिदृश्य को भविष्य-तैयार और अधिक न्यायसंगत बना सकता है। लेकिन यदि इनका क्रियान्वयन कमजोर रहा, तो यह वही कहानी दोहराएगा— यानि बड़े वादों के नीचे दबा हुआ श्रमिक का वास्तविक संघर्ष।

प्रेरणा

प्रकाश की अनंत खोज और सिद्धार्थ का आत्मजागरण

राजकुमार सिद्धार्थ की कथा समय की सीमाओं से परे है। यह उस मनुष्य की कहानी है जो जीवन के अर्थ को केवल देखा–सुना नहीं चाहता था, बल्कि स्वयं अनुभव करना चाहता था। यह कहानी उस खोज की है जो बाहरी वैभव से शुरू होकर अंततः आंतरिक प्रकाश तक पहुँचती है। जब एक राजकुमार अपने भीतर उठने वाले सूक्ष्म प्रश्नों को दबा नहीं पाया, तब इतिहास ने एक नई दिशा पकड़ ली। उसकी यात्रा ने संसार को करुणा, संतुलन और सम्यक् दृष्टि का वह दीप दिया, जो आज भी अंधेरे में दिशा दिखाता है।

सिद्धार्थ का बचपन महलों की सुरक्षा में बीता। पिता ने संसार के दुःखों को उनसे पूर्णतः दूर रखा था, ताकि उनका मन किसी भी प्रकार के वैराग्य से न भरे। महल में संगीत, नृत्य, उत्सव, पुष्प-वर्षा, सुगंधित गलियाँ—सब कुछ था, सिवाय वास्तविकता के। परंतु मनुष्य का हृदय एक बंद कक्ष में भी सत्य की दस्तक सुन ही लेता है। जब वे पहली बार नगर भ्रमण पर निकले, उन्होंने बुढ़ापे की कमज़ोरी, रोग की पीड़ा और मृत्यु की निश्चलता देखी। ये दृश्य उनके मन में उस प्रश्न की तरह उतर गए जिसका उत्तर कहीं बाहर नहीं, भीतर ही मिल सकता था। चौथा दृश्य—एक शांत संन्यासी का निर्मल चेहरा—उन्हें बता गया कि दुःख का उत्तर त्याग में, सत्यान्वेषण में और आत्मजागरण में छिपा है।

इन्हीं विचारों की आँधी ने उन्हें एक रात महलों से दूर कर दिया। उन्होंने अपनी राजकीय पोशाक उतार दी और अपने बाल काट दिए। अब वे न राजकुमार थे, न कोई विलासी व्यक्ति—वे केवल एक साधक थे, जो सत्य को जानना चाहता था। अनेक वर्षों तक उन्होंने गुरुओं के मार्गदर्शन में तप, ध्यान और योग का अभ्यास किया। परंतु जो ज्ञान वे सीख रहे थे, वह मन की गहराई तक नहीं उतर रहा था। प्रश्नों की छाया बनी हुई थी।

धीरे–धीरे साधना कठोर से कठोर होती गई। उन्होंने स्वयं को भोजन से दूर रखा, दिन–रात ध्यान में डूबे रहे, शरीर को इतना कमजोर किया कि वे एक साधारण हवा के झोंके से भी डगमगा सकते थे। उनके साथियों को लगता था कि सिद्धार्थ सत्य के करीब पहुँच रहे हैं, पर उनके भीतर कोई आवाज़ कहती थी कि कुछ मूलभूत अभी भी छूट रहा है। क्या आत्मा का जागरण शरीर को समाप्त कर देने से होता है? क्या सत्य केवल त्याग की अतिशयता में मिलता है?

इसी मोड़ पर सुजाता की भूमिका इस कहानी में प्रवेश करती है। सुजाता एक साधारण ग्रामबाला थी, पर उसके हृदय में श्रद्धा और सरलता का प्रकाश था। वह प्रतिदिन सिद्धार्थ के लिए खीर लाती थी, यह सोचकर कि वह कोई दिव्य तपस्वी है जिसे भोजन अर्पित करने से पुण्य मिलता है। सिद्धार्थ दिन-प्रतिदिन उस खीर को अनछुआ ही रहने देते। उनके भीतर का द्वंद्व उन्हें इतना कठोर बना चुका था कि उन्होंने खुद को हर प्रकार के सहारे से दूर कर लिया था।

एक दिन पूर्णिमा की उजास में, जब सुजाता खीर लेकर आई और सिद्धार्थ चुपचाप बैठे रहे, तभी पास के रास्ते से कुछ युवतियाँ एक लोकगीत गाती हुई निकलीं। गीत की पंक्तियाँ वीणा के तारों की मध्यमता पर आधारित थीं—"तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए, इतना भी मत ढीला छोड़ो कि स्वर ही न निकल पाए।" यह गीत सिद्धार्थ के मन पर बिजली की तरह गिरा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वे अपनी साधना में केवल अत्यधिक कसाव के मार्ग पर चले जा रहे थे। जैसे कोई वीणा का तार अधिक कसने से टूट जाता है, वैसे ही शरीर भी जीवन-योग्य नहीं रह सकता यदि उसे अत्यधिक कष्ट दिए जाएँ। एक ही पल में मानो एक नया द्वार खुल गया। उनके भीतर गूँजता हुआ प्रश्न अपने उत्तर में बदलने लगा। सत्य संतुलन में है, न अति में। न विलासिता में, न व्रत-जैसी कठोरता में। जीवन का स्वर तभी निकलता है जब मन और देह दोनों मध्यम पथ पर चलें। उन्होंने उसी क्षण सुजाता की खीर स्वीकार की। खीर उनके शरीर में नहीं, उनके चेतन में समा गई। उनके भीतर एक नई ऊष्मा जगी, और विचारों में एक असाधारण स्पष्टता आई। वे समझ चुके थे कि तपस्या और भोग दोनों ही चरम हैं—दोनों ही मन और आत्मा को असंतुलित कर देते हैं। अब सिद्धार्थ ने जीवन का नया मार्ग पकड़ा—संतुलन, सजगता और मध्यमता का मार्ग। वे बोधि-वृक्ष के नीचे पहुँचे और दृढ़ निश्चय के साथ ध्यान में बैठे। रात बीती, और ध्यान के चारों पहरों के साथ वे धीरे-धीरे जन्म-मरण के रहस्यों को देख पाने लगे। पहले पहर में उन्हें अपने अतीत दिखे—जन्मों की परतें खुलीं। दूसरे पहर में उन्होंने संसार के क्रियाकलापों का सूक्ष्म विज्ञान देखा। तीसरे पहर में उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म का पूरा चक्र समझा। और चौथे पहर में, जब भोर की सुनहरी किरणें आकाश को आलोकित करने लगीं, सिद्धार्थ के भीतर अंतिम अज्ञान भी टूट गया।

अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे—वे बुद्ध बन चुके थे। उनका चेहरा शांत था, उनकी दृष्टि गहरी थी और उनके भीतर ऐसा प्रकाश था जो किसी दीपक या सूर्य का नहीं, बल्कि शुद्ध बोध का था। उन्होंने जान लिया था कि दुःख का कारण इच्छा है, उसके नाश का मार्ग संयम है, और मुक्ति का दरवाज़ा मध्यम मार्ग है—जहाँ न कोई अतिशय त्याग है, न कोई अतिशय भोग। बुद्ध की यह यात्रा विश्व को यह सिखाती है कि सत्य तक वही पहुँचता है जो संतुलन को समझता है। जीवन की वीणा तब ही मधुर ध्वनि देती है जब उसके तार न टूटे हों, न ढीले पड़े हों—जब वे मध्यमता की सुंदर धुन पर झूमते हों। यही बुद्ध का प्रकाश है, यही उनकी विरासत—जो सदियों से मानवता का पथ आलोकित कर रही है।

पूरी की जाए सस्ते कर्ज की जरूरत, निवेशकों का भरोसा जरूरी

महंगाई में आई गिरावट ने सस्ते कर्ज की नई संभावनाओं को जन्म दिया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बीते अक्टूबर में खुदरा महंगाई घटकर पिछले दस वर्षों के न्यूनतम स्तर 0.25 प्रतिशत पर आ गई, जबकि थोक महंगाई भी 27 महीने के निचले स्तर यानी शून्य से 1.21 प्रतिशत नीचे दर्ज की गई। यह गिरावट मुख्यतः सब्जियों, फलों, अंडों, फुटवियर, अनाज एवं उससे बने उत्पादों के साथ बिजली, परिवहन और संचार सेवाओं की कीमतों में कमी के कारण संभव हुई है। सितंबर से लागू जीएसटी दरों में कटौती का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे खाद्य वस्तुओं के दाम सर्वत्र कम हुए हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में शाकाहारी थाली 17 प्रतिशत सस्ती होकर 27.8 रुपये की कीमत पर और मांसाहारी थाली 12 प्रतिशत सस्ती होकर 54.4 रुपये की दर पर उपलब्ध रही।

अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में औसत खुदरा महंगाई घटकर 2.5 प्रतिशत पर स्थिर रह सकती है, जो पिछले वर्ष की 4.6 प्रतिशत दर की तुलना में काफी कम है। इससे अगले महीने होने वाली आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति बैठक में नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है, ताकि विकास को नई गति मिल सके। इन दिनों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट में यह बात रेखांकित की जा रही है कि टैक्स और महंगाई में गिरावट से भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ रही है तथा देश की क्रेडिट रेटिंग भी सुधर रही है। इसके बावजूद तीव्र आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए कर्ज सस्ता करने की आवश्यकता बनी हुई है। मूडीज की ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऊंचे आयात शुल्क लगाए जाने के बावजूद कम महंगाई और आर्थिक आधारभूत मजबूती के चलते भारत चालू वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ जी-20 देशों में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

मूडीज ने आरबीआइ की सतर्क मौद्रिक नीति की भी सराहना की है, जिसने वृद्धि और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखा है। रिपोर्ट बताती है कि बीते महीने आरबीआइ ने रेपो दर को स्थिर रखकर यह संकेत दिया कि कम महंगाई और मजबूत विकास की परिस्थिति में वह सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रहा है। हालांकि निजी क्षेत्र अभी भी बड़े पैमाने पर निवेश को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं लगता। ऐसे समय में वैश्विक विकास दर में सुस्ती और अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी के बीच उद्योग-व्यापार के लिए सरल वित्त व्यवस्था की आवश्यकता और अधिक उभरकर सामने आई है।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी की मध्य-वर्षीय समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी दरों में कटौती और महंगाई में कमी से भारतीय अर्थव्यवस्था को स्पष्ट लाभ हुआ है, किंतु वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए उद्योग-व्यापार को वित्तीय समर्थन देना आवश्यक है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट भी यही कहती है कि वर्ष 2047 तक भारत को 30,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार और आसान ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

आरबीआइ इस वर्ष फरवरी, अप्रैल और जून में रेपो दर में कुल एक प्रतिशत की कटौती कर चुका है, जिससे यह अब 5.5 प्रतिशत पर आ गई है। साथ ही नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) भी घटाकर तीन प्रतिशत कर दिया गया है। फिर भी मौजूदा वैश्विक चुनौतियों और भारतीय उद्योग-व्यापार की आवश्यकताओं को देखते हुए ब्याज दरों में और कटौती समय की मांग है। वैसे भी वित्तीय संकेतक लगातार सुधार दिखा रहे हैं और विदेशी संस्थागत निवेशक दोबारा भारतीय बाजारों में निवेश बढ़ा रहे हैं। विश्व के कई केंद्रीय बैंक भी ब्याज दरों में कमी कर रहे हैं।

ऐसे माहौल में सस्ते कर्ज से देश में आर्थिक गतिविधियों को तीव्र गति मिल सकती है। ट्रंप टैरिफ और वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की रणनीतिक तैयारी को देखते हुए आसान कर्ज उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में नई ऊर्जा भर सकता है। घटी हुई ब्याज दरें न केवल निवेशकों के विश्वास को बढ़ाएंगी, बल्कि नवाचार, उत्पादन और बाजार विस्तार के लिए भी नया आधार तैयार करेंगी। विदेशी निवेश को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ग्रामीण और शहरी मांग में तेजी आएगी, जिससे विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी।

किफायती कर्ज की उपलब्धता से घरेलू बाजारों को गति मिलेगी और बैंकिंग प्रणाली भी अधिक स्थिर होगी। ईएमआइ घटने से उपभोक्ताओं की खर्च योग्य आय बढ़ेगी, जिससे घर और वाहनों की मांग में वृद्धि होगी। रियल एस्टेट क्षेत्र, जो लंबे समय से धीमी बिक्री की चुनौती से जूझ रहा है, ब्याज दरों में कटौती से राहत महसूस करेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि खुदरा और थोक महंगाई में आई तीव्र कमी तथा जीएसटी में कटौती के सकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए आरबीआइ आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में कमी का महत्वपूर्ण निर्णय लेगा। इससे उद्योग-व्यापार की गति बढ़ेगी, उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बाजार मांग में मजबूती और निवेश के नए माहौल को बल मिलेगा। साथ ही वैश्विक व्यापार अनिश्चितता एवं ट्रंप की टैरिफ चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ेगी।

अभियान

चन्द्र–मंगल का रहस्यमय संयोग: मन, आग, कर्म और भाग्य की अनकही कहानी

वैदिक ज्योतिष में चन्द्रमा और मंगल का एक ही घर में आकर मिल जाना केवल एक तकनीकी योग नहीं है, बल्कि यह दो शक्तियों का संयोग है— एक शक्ति जो मन की गहराइयों को नियंत्रित करती है, और दूसरी शक्ति जो भीतर छिपी अग्नि, साहस, क्रोध और कर्म को दिशा देती है। परंपरा कहती है कि जिन कुंडलियों में चन्द्रमा और मंगल साथ आते हैं, वहां किसी न किसी रूप में हलचल अनिवार्य है। जीवन ठहरा हुआ नहीं रह सकता। यह योग कभी महासागर जितना शांत धन देता है और कभी ज्वालामुखी जितना विस्फोटक कष्ट।

चन्द्रमा मन का प्रतिबिंब है—भावनाएं, संवेदनाएं, यादें, घर, माता, मन की तरंगें। मंगल कर्म का देवता है— रक्त, ऊर्जा, उत्साह, प्रतिरोध, क्रोध, प्रतियोगिता, सुरक्षा और संघर्ष। जब ये दोनों एक स्थान में आ जाते हैं, तो मन की गहराई और कर्म की शक्ति एक-दूसरे में घुलने लगती है, और यहीं से इस योग की कहानी शुरू होती है।

कभी यह संयोग किसी व्यक्ति को व्यापार में विलक्षण सफलता देता है, धन और जमीन-जायदाद का मालिक बनाता है, क्योंकि मंगल भूमि का और चन्द्रमा तरल धन का स्वामी माना गया है। यदि यह संयोग पंचम भाव में हो जाए तो बुद्धि चमक उठती है, विचारों की नदी निरंतर बहने लगती है, और जातक सृजनशीलता में उछाल महसूस करता है। कला, संगीत, लेखन, अभिनय या व्यापार—जो भी क्षेत्र चुने, वहां असाधारण उपलब्धियां संभव हैं। कोई व्यक्ति अचानक धनवान भी बन सकता है, क्योंकि चन्द्रमा और मंगल साथ मिलकर धनप्राप्ति में तेज गति लाते हैं। इसी संयोग के चलते कई लोग स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या व्यापार में रातोंरात तरक्की कर जाते हैं।

लेकिन यही संयोग जब अशुभ हो— चन्द्रमा पीड़ित हो जाए या मंगल दूषित हो जाए—तो इसके परिणाम उतने ही उलटे पड़ते हैं। किसी भी घर में यह स्थिति मानसिक तनाव, बेचैनी, क्रोध, आवेग या बंटे हुए निर्णय पैदा कर सकती है। यदि यह योग दशम भाव में अशुभ रूप ले ले, तो व्यक्ति अनैतिक मार्ग अपनाकर धन जुटाने की कोशिश भी कर सकता है। इतिहास के कई कुख्यात माफिया, तस्कर, काला धन कमाने वाले, और ऐसे लोग जिनका मन और कर्म दोनों किसी छाया में लिपटे हों—उनकी कुंडलियों में इसी योग का अशुभ स्वरूप पाया गया है।

कई बार यह योग इतना विकृत हो जाता है कि जातक अपने ही परिवार को धोखा देने की हद तक गिर जाता है। कुछ लोग तो अवैध धंधों में ऐसे डूब जाते हैं कि अपनी बहनों या स्त्री रिश्तेदारों तक को गलत रास्तों पर धकेलने में भी नहीं हिचकते—ऐसा निर्दयी, कठोर और सांसारिक लालच से अंधा बनाया हुआ मंगल जब भावनाहीन, कमजोर चन्द्रमा से जुड़ जाता है, तब ऐसे दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं। यदि यह संयोग चतुर्थ भाव में अशुभ हो, तो विवाह में कड़वाहट घुल जाती है। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव, शक, तनाव और कभी-कभी शारीरिक हिंसा तक उत्पन्न हो सकती है। घर की शांति टूट जाती है, और व्यक्ति चाहे जितनी कोशिश करे, मानसिक स्थिरता हाथ में नहीं आती।

यही संयोग जब प्रथम भाव में बने—और चन्द्रमा शुभ हो पर मंगल पीड़ित—तो व्यक्ति मानसिक रोगों, चिंता, फोबिया, अवसाद या भावनात्मक उलझनों से गुजर सकता है। उसका शरीर चलता है, पर मन लड़खड़ाता रहता है। जबकि उलटी स्थिति—मंगल शुभ और चन्द्रमा अशुभ—किसी व्यक्ति को अवैध शक्ति का लोभी बना सकती है। ऐसे लोग हथियार, ब्लैक मार्केट, स्मगलिंग या छुपे हुए आपराधिक कार्यों की तरफ तेजी से आकर्षित होते हैं।

लेकिन चन्द्र–मंगल का रहस्य केवल इतना नहीं है—यह योग एक गहन आध्यात्मिक संदेश भी देता है। यह सिखाता है कि मन और ऊर्जा जब संतुलन में हों, तो मनुष्य असाधारण बन जाता है। पर यदि मन अशांत हो और ऊर्जा गलत दिशा में जाए, तो वही मनुष्य अपने ही जीवन को भस्म कर सकता है। यह योग वास्तव में एक परीक्षा है—एक मानसिक अग्निपरीक्षा। जिसने इसे साध लिया, वह विजेता हुआ; जिसने नियंत्रण खो दिया, वह जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष का शिकार बना।

इसलिए कुंडली में चन्द्र–मंगल योग होने पर केवल संयोग देखना पर्याप्त नहीं है। यह देखना आवश्यक है कि चन्द्रमा कैसा है—स्थिर या पीड़ित, शुभ या अशुभ, पूर्ण या क्षीण। मंगल कैसा है—ऊर्जा संतुलित है या भटकी हुई, न्यायप्रिय है या प्रतिशोधात्मक, कर्मवादी है या आवेगी। योग किस भाव में बैठा है, किस राशि में है, कौन-कौन से ग्रह इन्हें देख रहे हैं—यही सब इस योग के पूरे रंग बदल देते हैं।

अंत में यही कहा जा सकता है कि चन्द्र–मंगल योग एक ऐसी खिड़की है, जिसके बाहर या तो उजाला है या धधकती आग। यह योग धन दे सकता है, प्रसिद्धि दे सकता है, जमीन दे सकता है, व्यापार दे सकता है, बुद्धि दे सकता है—लेकिन इसी शक्ति की एक उलटी परछाईं गरीबी, मानसिक कष्ट, क्रोध, अपराध, हिंसा और अनैतिकता में भी बदल सकती है।

इसलिए किसी भी कुंडली का अंतिम निर्णय तभी किया जाना चाहिए जब चन्द्रमा और मंगल दोनों की दशा, दृष्टि, बल, अवस्था और राशि का सूक्ष्म निरीक्षण हो जाए, क्योंकि यह योग जितना चमकदार है, उतना ही भयावह भी बनने की क्षमता रखता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कांफ्रेंस बनेगा मोरबी सिरेमिक क्लस्टर के लिए नए वैश्विक अवसरों का द्वार

- मोरबी सिरेमिक क्लस्टर है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिरेमिक उत्पादन हब
- भारत-यूके CETA समझौते के तहत मोरबी के प्रमुख सिरेमिक निर्यातों को मिलेगी शून्य-शुल्क और टैरिफ-रहित बाजार की सुविधा
- FY 2024-25 में यूके को भारतीय सिरेमिक निर्यात तीन गुना बढ़कर 110 मिलियन डॉलर तक पहुँचा, जिसमें मोरबी का योगदान 65% (71.6 मिलियन डॉलर)
- मोरबी सिरेमिक क्लस्टर ने किए 3.5 लाख प्रत्यक्ष और करीब 10 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित
- आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कांफ्रेंस में मोरबी सिरेमिक की वैश्विक संभावनाओं और स्थानीय उद्यमिता को प्रदर्शित करने का मिलेगा अवसर

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र का मोरबी सिरेमिक क्लस्टर वैश्विक सिरेमिक उद्योग में एक नई पहचान गढ़ रहा है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सिरेमिक उत्पादन क्लस्टर के रूप में मोरबी आज अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहाँ 800 से अधिक निर्यात-उन्मुख यूनिट्स इसे एक सशक्त वैश्विक हब बनाती हैं। विकास और उद्यमशीलता के मजबूत इकोसिस्टम के साथ मोरबी क्लस्टर गुजरात की "विकसित भारत@2047" की यात्रा में निर्णायक भूमिका निभा रहा है और विश्वभर से बढ़ती सिरेमिक उत्पादों की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है।

यूके में भारतीय सिरेमिक की बढ़ती मांग, मोरबी ने संभाला नेतृत्व

पिछले 3-4 वर्षों में भारतीय सिरेमिक निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और यूके को निर्यात तीन गुना बढ़कर FY 2024-25 में 110 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया है, जिसमें मोरबी अकेले 65% यानी 71.6 मिलियन डॉलर का योगदान देता है। यह तेज़ वृद्धि यूके बाज़ार में पोर्सिलेन स्लैब, टाइल्स और क्वार्ट्ज उत्पादों जैसी प्रीमियम निर्माण सामग्रियों की बढ़ती मांग को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

सिरेमिक क्षेत्र की संभावनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, जिन्हें शहरीकरण की तेज़ रफ्तार, सरकारी आवास योजनाएँ और स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलों से और बल मिल रहा है। मोरबी का सिरेमिक और सैनिटरीवेयर उद्योग वॉल और फ्लोर टाइलों से लेकर विभिन्न बाथरूम एक्सेसरीज़ तक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण करता है। अपनी उत्कृष्ट उत्पादन क्षमता और निर्यात प्रदर्शन के आधार पर मोरबी को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सिरेमिक टाइल्स एवं सैनिटरीवेयर श्रेणी में "टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस" (TEE) का दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे इसकी वैश्विक पहचान और भी सशक्त हुई है।

मोरबी सिरेमिक क्लस्टर ने किए 3.5 लाख प्रत्यक्ष और करीब 10 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित

मोरबी का सिरेमिक क्लस्टर न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। यह क्लस्टर विनिर्माण इकाइयों में लगभग 3.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है और करीब 10 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही उद्योग ने लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, कच्चे माल की आपूर्ति जैसी सहायक क्षेत्रों में भी नई नौकरियों का सृजन किया है। मोरबी सिरेमिक क्लस्टर ने न केवल स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान किया है बल्कि अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों के लिए भी व्यापक अवसर सुनिश्चित किए हैं, जिससे यह क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत बन रहा है।

"मेड इन मोरबी" बन रहा वैश्विक ब्रांड

एक छोटे से शहर से वैश्विक निर्यातक बनने की यात्रा में मोरबी सिरेमिक क्लस्टर ने गुजरात को निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाने के साथ-साथ "मेड इन मोरबी" को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। मोरबी सिरेमिक उद्योग को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से विशेष लाभ मिला जिसकी अवधारणा 2003 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तैयार की गई थी। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में आयोजित होने वाला आगामी वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन मोरबी सिरेमिक क्लस्टर की संभावनाओं और स्थानीय उद्यमियों की ऊर्जा को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का अवसर प्रदान करेगा। यह प्रतिष्ठित आयोजन निवेश को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र की स्थानीय प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

भारत-यूके आर्थिक समझौता मोरबी सिरेमिक उद्योग के लिए बना नए अवसरों का द्वार

भारत सिरेमिक उत्पादों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है और वैश्विक बाज़ारों में अपनी मज़बूत पकड़ के साथ मोरबी इस क्षेत्र का प्रमुख आधार स्तंभ बनकर उभरा है। 24 जुलाई 2025 को भारत-यूके कोम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) पर हुए हस्ताक्षर गुजरात की औद्योगिक क्षमता और मोरबी सिरेमिक क्लस्टर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। यह ऐतिहासिक समझौता भारत के प्रमुख सिरेमिक निर्यातों के लिए शून्य-शुल्क और टैरिफ-रहित बाज़ार पहुँच सुनिश्चित करता है, जिससे मोरबी के उत्पादों के लिए यूके समेत वैश्विक बाज़ारों में नई संभावनाएँ खुल रही हैं।

पश्चिम रेलवे की फर्जी टिकटों पर सख्त कार्रवाई,अक्टूबर & नवंबर 2025 में कई मामलों का पता लगाया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षित, पारदर्शी व निष्पक्ष यात्रा सुनिश्चित करने के लिए फर्जी टिकटिंग के विरुद्ध अपनी सतर्कता को और मजबूत किया है। अक्टूबर–नवंबर 2025 के दौरान पश्चिम रेलवे के सतर्क टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा नकली मोबाइल टिकट, नकली आरक्षित टिकट तथा रियायतों के दुरुपयोग से जुड़े चार महत्वपूर्ण मामले पकड़े गए।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सभी मामलों में सख्त कार्रवाई की गई तथा संबंधित यात्रियों को आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु जीआरपी के सुपुर्द किया गया।

पहले मामले में टिकट चेकिंग स्टाफ प्रदीप कुमार ने ए.सी. उपनगरीय लोकल में एक डिजिटल रूप से संपादित मोबाइल टिकट पकड़ा, जिसमें 15/- के टिकट को डिजिटल एडिटिंग टूल्स का उपयोग कर फर्जी तरीके से सीज़न टिकट में बदल दिया गया था। नियमित चेकिंग के दौरान यह हेरफेर सामने आया, जिसके बाद यात्री को हिरासत में लेकर जीआरपी के हवाले

किया गया।

दूसरा मामला टिकट चेकिंग स्टाफ मोहम्मद जाहिद कुरैशी द्वारा एक लंबी दूरी की ट्रेन में पकड़ा गया। रियायत के लिए अपात्र दो यात्री विकलांग कोटा में बुक किए गए टिकटों पर यात्रा कर रहे थे। रियायत का लाभ लेने के लिए किराया विवरण में छेड़छाड़ की गई थी, जबकि यात्री इसके पात्र नहीं थे। दोनों यात्रियों को तुरंत जीआरपी को सौंप दिया गया।

तीसरा मामला टिकट चेकिंग स्टाफ मोहम्मद जाहिद कुरैशी और अब्दुल अज़ीज द्वारा संयुक्त रूप से एक मेल/एक्सप्रेस ट्रेन में पकड़ा गया। एक नकली तत्काल आरक्षित टिकट, जो एक अनधिकृत एजेंट से अधिक दर पर खरीदा गया था, जांच के दौरान पाया गया। यात्री ने इसे अवैध तरीके से प्राप्त करने की बात स्वीकार की, जिसके बाद उसे जीआरपी के सुपुर्द किया गया।

चौथे मामले में टिकट चेकिंग स्टाफ साई प्रसाद ने ए.सी. उपनगरीय लोकल में डिजिटल रूप से संपादित मोबाइल टिकट पकड़ा। इसमें क्यूआर कोड और प्रमुख टिकट विवरणों से अनधिकृत ग्राफिक टूल्स का उपयोग कर छेड़छाड़ की गई थी। निरीक्षण में टिकट फर्जी पाए जाने के बाद संबंधित यात्री को हिरासत में लेकर जीआरपी कर्मियों को सौंप दिया गया।

पश्चिम रेलवे की यात्रियों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत माध्यमों, जैसे यूटीएस ऐप, आईआरसीटीसी ऐप, पीआरएस/यूटीएस बुकिंग काउंटर आदि से ही टिकट खरीदें, ताकि वास्तविक यात्रा दस्तावेज सुनिश्चित हों तथा फर्जीवाड़े से बचाव हो सके।

मेलोडी मेकर्स ग्रुप ने 'म्यूज़िक मौज मस्ती' से की नव वर्ष की शानदार शुरुआत!

(जीएनएस)। मेलोडी मेकर्स ने दीपावली के बाद इस नव वर्ष में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत 'म्यूज़िक मौज मस्ती' टाइटल से की और श्रोताओं का मन जीता। गीत-संगीत के इस शानदार कार्यक्रम में सभी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दीं। मेलोडी मेकर्स ग्रुप का प्रयास हमेशा यह रहता है कि उम्र कोई भी हो, कलाकार को सम्मान और एक अच्छा मंच दिया जाए। साथ ही, कला के प्रति समर्पण भाव रखने वाले श्रोताओं का ध्यान रखते हुए ही कार्यक्रम किए जाएं। अपने नौवें वर्ष में मेलोडी मेकर्स ग्रुप इसी प्रयासों में लगातार निरंतर सफलतापूर्वक अग्रसर है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नई नियुक्ति पाने वाले 4400 से अधिक युवाओं का आह्वान

राज्य सरकार में मिले नौकरी के अवसर को केवल नियुक्ति के रूप में नहीं, बल्कि आम आदमी की सेवा से राष्ट्र निर्माण में योगदान के अवसर के रूप में स्वीकारें

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुड गवर्नेंस के लिए ट्रांसपरेंसी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग तथा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर जो फोकस किया है, उसे गुजरात ने सरकार के विभिन्न विभागों में पारदर्शी नियुक्ति से साकार किया है
- राज्य सरकार द्वारा कार्यरत किया गया कैडर मैनेजमेंट पोर्टल तथा 10 वर्षीय भर्ती कैलेंडर भविष्य के मैन पावर रिक्रूटमेंट आयोजन के लिए महत्वपूर्ण बना है
- **राज्य सरकार के विभिन्न संवर्गों में वर्ग-3 में नई नियुक्ति प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का गौरवशाली समारोह गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा मंत्रियों की उपस्थिति में संपन्न**
- **उप मुख्यमंत्री का राज्य के नागरिकों की सेवा के लिए मिले अवसर का उपयोग नागरिकों की आशाएँ परिपूर्ण करने तथा सकारात्मकता से हो; इसका ध्यान रखने का अनुरोध**
- **इस महीने के अंत तक गुजरात पुलिस बल में कुल 14,507 नई रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया घोषित की जाएगी : उप मुख्यमंत्री**

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के विभिन्न संवर्गों में वर्ग-3 में नई नियुक्ति प्राप्त कर रहे 4,473 युवाओं का आह्वान किया है कि वे राज्य सरकार की सेवा में उन्हें मिले अवसर को केवल नई नियुक्ति के रूप में नहीं, बल्कि आम आदमी की सेवा से राष्ट्र निर्माण में योगदान के अवसर के रूप में स्वीकारें।

इस संदर्भ में श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार में 'नागरिक देवो भवः' का मंत्र अपनाया है और लोगों को गुड गवर्नेंस की निरंतर प्रतीति कराई है। उन्होंने कहा कि नई नियुक्ति पा रहे युवाओं से अपेक्षा है कि वे भी प्रामाणिकता के साथ कार्यरत रहकर, किसी छोटे आदमी की मुश्किल दूरकर या किसी विधवा माता के आँसू पोंछकर तथा निराधार का आधार बनकर अपने वाणी-बर्ताव एवं व्यवहार से लोगों को संवेदनशील सरकार की अनुभूति कराएँ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की विशेष उपस्थिति में शनिवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 'विकसित भारत, विकसित गुजरात' अंतर्गत गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन मंडल (गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड यानी जीएसएसएसबी) द्वारा सरकार के विभागों में विभिन्न कैडर में चयनित कुल 4,473 उम्मीदवारों में से लगभग 21 उम्मीदवारों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रेरणा देते हुए कहा कि वे ड्यूटी और कार्य में शिथिलता नहीं, बल्कि नवीनता के दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रहित प्रथम एवं राज्य के विकास से राष्ट्र के विकास के भाव को समग्र कॅरियर में प्राथमिकता देकर 2047 के विकसित भारत के निर्माण के संवाहक बनें।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुड गवर्नेंस के लिए ट्रांसपरेंसी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर जो फोकस किया है, उसे गुजरात ने पारदर्शी नियुक्ति से साकार किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा मानव संसाधन के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग से कार्यरत किए गए 3000 से अधिक कैडर की जानकारी से युक्त कैडर मैनेजमेंट पोर्टल तथा 10 वर्षीय भर्ती कैलेंडर का विवरण दिया। इसके परिणामस्वरूप मैन पावर रिक्रूटमेंट का आयोजन सरल बना है। रोजगार वांछु युवाओं को भी परीक्षा की अग्रिम जानकारी मिलती है और वे पूर्ण तैयारी कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुए रोजगार मेलों से देश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अतिरिक्त निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में 'हर हाथ को काम, हर काम का सम्मान' का ध्येय साकार करने वाले रोजगार के अवसर खुले हैं तथा 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री के विजन से 'पीएम विकसित भारत योजना' शुरू हुई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नई नियुक्ति पा रहे युवाओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित कीं।उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का गुजरात सरकार परिवार में स्वागत-सह-अभिनंदन करते हुए कहा कि आज का दिन गुजरात की युवा शक्ति के लिए एक स्वर्णिम दिवस है। आज जब सभी उम्मीदवारों ने अथक परिश्रम के अंत में यह उपलब्धि प्राप्त की है, तब उनके माता-पिता एवं परिवार के सदस्यों के सपने भी साकार हुए होंगे। यह सफलता जनसेवा की नई शुरुआत है। नई नियुक्ति पाने वाले सभी उम्मीदवारों को राज्य के नागरिकों के काम करने के लिए अवसर मिला है। उन्होंने इस अवसर का उपयोग नागरिकों की सेवा करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हो; इसका ध्यान रखने का अनुरोध किया।

श्री संघवी ने कहा कि अप्रैल-2025 से अब तक गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन मंडल द्वारा लगभग 101 परीक्षाएँ आयोजित कर रिकॉर्ड बनाया गया है। उन्होंने ऑनलाइन, पारदर्शी एवं त्वरित भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने वाले गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन मंडल की समग्र टीम को अभिनंदन दिया।

उन्होंने इस अवसर पर महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियाँ करने वाले राज्य के लाखों युवाओं के लिए इसी महीने के अंत तक गुजरात पुलिस बल में 14,507 नई रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया घोषित की जाएगी। इनमें पुलिस उप निरीक्षक (पीएसआई) तथा लोकरक्षक जैसे मुख्य कैडर की 13,591 रिक्तियाँ तथा टेक्निकल कैडर की 916 रिक्तियाँ शामिल हैं। इसके अलावा, हाल में गुजरात पुलिस बल की 12 से अधिक रिक्तियों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है, जिसके नियुक्ति पत्र भी शीघ्र दिए जाएंगे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संदेश के माध्यम से नवनियुक्त उम्मीदवारों को अभिनंदन देकर 'विकसित भारत' के लिए अपना अधिकतम योगदान देने की शुभकामनाएँ दीं। मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने स्वागत संबोधन में कहा कि प्रत्येक युवा का सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सपना होता है और आज का दिन उस सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन मंडल द्वारा यह भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी ढंग से करके सभी चरणों में आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में आँगनबाड़ी तथा पुलिस विभाग में निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों को अभिनंदन देते हुए कहा, "आप सभी भाग्यशाली हैं कि राज्य सरकार की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के कालखंड के दौरान आपकी भर्ती हो रही है। आपके कार्यकाल में भारत विकास की नई दिशाएँ पार करने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सब इसमें अपना अधिकतम योगदान देंगे।" राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि ने इस अवसर पर उपस्थित सभी का आभार व्यक्त कर नवनियुक्त उम्मीदवारों को शुभकामनाएँ दीं। राज्यभर से चयनित उम्मीदवारों में सर्वाधिक जूनियर क्लर्क वर्ग-3 में 2828 के अलावा सब रजिस्ट्रार ग्रेड 1-2 की कुल 92, स्टाम्प निरीक्षक वर्ग-3 की कुल 22, वरिष्ठ लिपिक वर्ग-3 की 339, प्रधान लिपिक वर्ग-3 की 138, सहायक समाज कल्याण अधिकारी वर्ग-3 की कुल 20, समाज कल्याण निरीक्षक वर्ग-3 की 144, गृहपति, कार्यालय सहायक, आगार प्रबंधक, सहायक आगार प्रबंधक, सहायक आदिजाति विकास अधिकारी वर्ग-3, लेखपाल वर्ग-3 तथा सर्वेक्षक की कुल 882 सहित कुल 4473 रिक्तियाँ शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वडनगर में ताना-रीरी महोत्सव का भव्य शुभारंभ कराया

- **मुख्यमंत्री का संगीत कला की स्वदेशी विरासत के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान**
- **मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री कलापिनी कोमकली को ताना-रीरी संगीत सम्मान अवॉर्ड प्रदान किया**

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय संस्कृति के 2000 वर्षों के इतिहास को संजोए बैठे वडनगर में ताना-रीरी महोत्सव 2025 का शनिवार को शुभारंभ कराया। यह महोत्सव खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ विभाग अधीनस्थ गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी-गांधीनगर तथा मेहसाणा जिला प्रशासन के संयुक्त उपक्रम से हर वर्ष आयोजित किया जाता है। शनिवार को महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री कलापिनी कोमकली को प्रतिष्ठित ताना-रीरी संगीत सम्मान अवॉर्ड प्रदान किया गया।

श्री पटेल ने इस अवसर पर कहा कि वडनगर की भूमि में ही कुछ ऐसा सत्व-तत्व रहा है कि अनादिकाल से यहाँ समर्पण एवं सेवा साधना की पराकाष्ठा विकसित हुई है। उन्होंने ताना-रीरी को अनमोल संगीत कला विरासत का उत्तम उदाहरण बताते हुए कहा कि उनकी तरह ही वडनगर के सपूत एवं विश्व नेता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी राष्ट्र प्रथम के भाव से कार्यरत रहकर देश तथा दुनिया के समक्ष सेवा साधना का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कला एवं स्थापत्य की इस नगरी के इतिहास को पुनर्जीवित करने के सफल आयाम का सूत्रपात किया है। श्री पटेल ने प्रधानमंत्री की विरासत संवर्धन नीतियों का विवरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जहाँ प्राथमिक शिक्षा ली, उसे प्रेरणा स्कूल के रूप में विकसित किया है। जहाँ उन्होंने बचपन में परिश्रम की पराकाष्ठा सृजित की, उस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है और मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा वडनगर की समग्र पुरातन विरासत को प्रस्तुत करने वाले अत्याधुनिक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम का भी वडनगर में निर्माण हुआ है।

स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत वडनगर में हुए विकास की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना अंतर्गत शर्मिष्ठा तालाब, ताना-रीरी पार्क, लटेरी वाव (बावड़ी), अंबाजी कोठा तालाब तथा फोर्ट वॉल का विकास किया जा रहा है, जबकि पौराणिक हाटकेश्वर मंदिर का इतिहास लोग जान सकें; इसके लिए लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया गया है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय संगीत विरासत की समृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि आज रोग के उपचार के लिए भी म्यूजिक थेरेपी का उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी विरासत का युगों तक जतन एवं संवर्धन करने का संकल्प किया है।

वर्ष 2047 में विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को कला-संस्कृति

के साथ जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा है कि कला-संस्कृति की स्वदेशी विरासत का संरक्षण हो और आने वाली पीढ़ी को भी इस विरासत के जतन की प्रेरणा मिले। मुख्यमंत्री ने सभी का आह्वान किया कि वडनगर की पवित्र धरती से इस कला-संस्कृति के जतन के साथ स्वदेशी अपना कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध हों।

संगीत समारोह में अवॉर्ड विजेता सुश्री कलापिनी कोमकली, प्रसिद्ध सितार वादक श्री निलाद्री कुमार तथा गायिका सुश्री ईशानी दवे ने शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन तथा लोक गीतों की सुमधुर प्रस्तुति से वडनगर को संगीतमय बना दिया।

भक्त कवि नरसिंह मेहता की दोहित्री शर्मिष्ठा की सुपुत्रियों ताना तथा रीरी ने मल्हार राग गाकर संगीत सम्राट तानसेन के दीपक राग से उत्पन्न हुए दाह को शांत किया था। उसकी स्मृति में तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2003 में ताना-रीरी महोत्सव तथा वर्ष 2010 में ताना-रीरी संगीत सम्मान अवॉर्ड की शुरुआत की गई थी।

ताना-रीरी महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर केबिनेट मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी व श्री ऋषिकेश पटेल, सामाजिक अग्रणी श्री सोमाभाई मोदी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री तृषाबेन पटेल, विधायक सर्वश्री के. के. पटेल (ऊंझा), सरदारभाई चौधरी (खेरालू), सुखाजी ठाकोर (बहुचराजी), राजेन्द्र चावडा (कडी), वडनगर नगर पालिका अध्यक्ष सुश्री मितिका शाह, गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार पांडे, जिला कलेक्टर श्री एस. के. प्रजापति, जिला विकास अधिकारी डॉ. हसरत जैस्मीन, गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी के सदस्य सचिव श्री आई. आर. वाळा, निवासी अपर कलेक्टर श्री जसवंत जेगोडा सहित वडनगर व मेहसाणा के अग्रणी तथा बड़ी संख्या में नगरजनों ने सुमधुर संगीत का आनंद उठाया।

नई डोर, नया भरोसा: हैदराबाद में मध्यप्रदेश को मिला 36,600 करोड़ का निवेश, सीएम मोहन यादव बोले-निवेशकों के साथ जोड़ने आए हैं नई डोर”

(जीएनएस)। हैदराबाद की हलचल से भरी रोशनी और तेज़ी से दौड़ती महत्वाकांक्षाओं के बीच शनिवार का दिन मध्यप्रदेश के लिए किसी नए युग की शुरुआत जैसा साबित हुआ। यहां आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्यप्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव न सिर्फ निवेशकों से रूबरू हुए, बल्कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जिसमें आर्थिक सहयोग एक भावनात्मक रिश्ता बनकर उभरा। बात सिर्फ निवेश आकर्षित करने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे भरोसे की थी जिसे सीएम यादव बार-बार “नई डोर” कहकर संबोधित करते रहे। उन्होंने कहा—“हम हैदराबाद इसलिए नहीं आए कि सिर्फ उद्योगपतियों से मुलाकात कर लें हम आए हैं ताकि एक ऐसी डोर बांध सकें जो विकास को गंतव्य तक ले जाए।”

कार्यक्रम में हैदराबाद के उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश के लिए जो उत्साह दिखाया, वह राज्य की बदलती सूरत का प्रमाण बना। एक ही दिन में 36,600 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए और इससे 27,800 से अधिक नए रोजगार सृजित होने की संभावना जताई गई। यह आंकड़ा केवल कागज़ पर दर्ज कोई संख्या नहीं, बल्कि उन बदलावों की गवाही है जो मध्यप्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में निरंतर दिखाई दे रहे हैं—नवीन नीतियां, तेज़ प्रशासन, पारदर्शी प्रक्रियाएँ और उतना ही आत्मविश्वास से भरा नेतृत्व।

मोहन यादव ने अपने संबोधन में निवेशकों को आश्वस्त किया कि मध्यप्रदेश सिर्फ नीतियों से नहीं बल्कि मन से स्वागत करता है। उन्होंने एक रोचक और भावनात्मक उदाहरण दिया—“हम महाकाल की नगरी से आते हैं, जहां धरती से हीरा निकलता है। तेलंगाना मोतियों की धरती है। इसलिए हमारी जोड़ी हीरा-मोती की तरह है—मिलकर चमक पैदा करने वाली।” सभागार तालियों से गूंज उठा, और इस गूंज में उद्योगपतियों का विश्वास महसूस

किया जा सकता था।

सीएम ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश ने अपनी 18 नई निवेश नीतियों से एक ऐसा वातावरण तैयार किया है, जिसमें निवेशक रुककर नहीं, बल्कि दौड़कर आते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार नीतियों की परिधि से बाहर जाकर भी उद्योगों की मदद करेगी। “हम पलक-पांवड़े बिछाकर आपका स्वागत करने आए हैं,” यह वाक्य महज़ राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि वेज्यन और वचन का संगम था।

कार्यक्रम का अहम पक्ष यह था कि कई उद्योगपतियों ने अपना अनुभव खुलकर साझा किया। ग्रीनको ग्रुप के महेश कोली ने बताया कि सवा तीन वर्षों में 1,900 मेगावॉट का हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पूरा करना किसी चमत्कार से कम नहीं—“कहीं और होता तो दस साल लग जाते।” सुधाकर पाइप्स के जयदेव मीला ने बताया कि जमीन, औपचारिकताओं और प्रक्रिया को जिस गति से मध्यप्रदेश में पूरा किया गया, वह देश में कहीं नहीं मिलता। अनंत टेक्नोलॉजीज़ के डॉ. सुब्बाराव ने स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी राज्य की स्पष्ट नीतियों और तेज़ प्रशासनिक फैसलों की खुलकर तारीफ की।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को यह भी बताया कि मध्यप्रदेश अब सिर्फ पारंपरिक उद्योगों का नहीं, बल्कि टियर-2 टेक हब बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है। इंदौर–भोपाल का उभरता इकोसिस्टम, सस्ती बिजली, कम लागत, उच्च प्रतिभा—ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जिसकी तुलना देश के किसी बड़े मेट्रो से की जा सकती है। 2000 एकड़ में प्रस्तावित नॉलेज सिटी इसका एक बड़ा उदाहरण है, जो वैश्विक यूनिवर्सिटीज और टेक कंपनियों को एक छत के नीचे लाएगी।

चर्चाओं के बाद जो निवेश प्रस्ताव सामने आए, उनमें 29,500 करोड़ रुपये का नवीकरणीय ऊर्जा निवेश, 1,500 करोड़ का पैकेजिंग इंजीनियरिंग यूनिट, 1,000–1,000 करोड़ की एयरोस्पेस और आईटी सेक्टर में परियोजनाएँ, फूड प्रोसेसिंग, कृषि, फार्मा, ट्रेडिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां शामिल थीं। यह विविधता दिखाती है कि मध्यप्रदेश अब केवल उद्योगों को आकर्षित नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें एक व्यापक भविष्य की ज़मीन दे रहा है। यह आयोजन सिर्फ एक सम्मेलन नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंच बना जिसने स्पष्ट कर दिया कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा से ज्यादा सहयोग की भावना बढ़ रही है। सीएम यादव ने कहा—“यह समय है सरकारी व्यवस्था के माध्यम से स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का। हम विकास को किसी चुनावी एजेंडे से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व के रूप में देख रहे हैं।” हैदराबाद में उनकी यह मौजूदगी मध्यप्रदेश के लिए एक ऐसे नए अध्याय की शुरुआत बन गई है जहाँ निवेश केवल पूँजी का प्रवाह नहीं, बल्कि भरोसे और साझेदारी की नई कहानी लिख रहा है। और इस कहानी में यह वाक्य उनकी यात्रा की पहचान बन गया— “हम निवेश मांगने नहीं आए हम संबंध बनाने आए हैं।”

उदयपुर में शाही शादी का अनोखा नज़ारा: आमेर से आया खास हाथी, दूल्हा वामसी इसी पर बैठकर निभाएंगे तोरण की रस्म, दुल्हन नेत्रा मंटेना की रॉयल वेडिंग में बॉलीवुड-हॉलीवुड का जमावड़ा

(जीएनएस)। उदयपुर। झीलों की नगरी इन दिनों किसी राजसी उत्सव की तरह जगमगा रही है। अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शादी ने उदयपुर की भव्यता में सुनहरी चमक भर दी है। हल्दी से लेकर संगीत और अब वेडिंग फंक्शन तक—हर रस्म एक ऐसे शाही अंदाज़ में हो रही है, जिसे देखने के लिए बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की हस्तियां पहुंच चुकी हैं। सितारों की परफॉर्मेंस, दावतों का शाही स्तर और झीलों के बीच जगमगाते महलों के बीच यह शादी किसी फ़िल्मी दृश्य से कम नहीं लग रही।

सबसे ज़्यादा चर्चा दूल्हे वामसी गडिराजू की तोरण रस्म की हो रही है, क्योंकि इस रस्म को निभाने के लिए एक खास हाथी को आमेर से उदयपुर लाया गया है। यह हाथी—जिसे प्यार से ‘हाथी बाबू’ कहा जाता है—राजस्थान के आमेर स्थित हाथी गांव का एकमात्र नर हाथी है, जिसकी मजबूती, विशाल कद-काठी और आकर्षक रूप ने उसे खास पहचान दी है। आयोजकों ने इस हाथी को तीन महीने पहले ही बुक कर लिया

था, लेकिन हाथी के मालिक को यह पता ही नहीं था कि यह बुकिंग किस बड़े आयोजन के लिए की गई है। सिर्फ एक हफ्ते पहले फोन पर जानकारी दी गई कि हाथी को एक ऐसी शादी में बुलाया जा रहा है, जहां दुनिया भर की निगाहें टिकी होंगी।

हाथी बाबू की सबसे अनोखी विशेषता उसके लगभग डेढ़ फीट लंबे हाथीदांत हैं। दूर से ही दिखाई देने वाले ये सफेद और चमकते दांत उसे किसी राजसी शक्ति का रूप देते हैं। आयोजकों का मानना है कि यही खूबसूरती और उसका शाही व्यक्तित्व उसे इस खास रस्म के लिए बिल्कुल सही बनाता है। दूल्हा वामसी इसी हाथी पर सवार होकर तोरण तक पहुंचेंगे—एक दृश्य जो इस शादी की शाही भव्यता को और ऊंचाई दे देगा। मेहमानों के लिए भी यह क्षण किसी ऐतिहासिक महफ़िल का हिस्सा बनने जैसा होगा।

21 नवंबर से शुरू हुए इस उत्सव में हर रस्म अपने आप में एक भव्य आयोजन के रूप में दिखाई दे रही है। गुरुवार की शाम लीला पैलेस में दोनों परिवारों का वेलकम डिनर हुआ, जहां सितारों की मौजूदगी ने माहौल को और अधिक जगमगा दिया। शुक्रवार को ताज लेक पैलेस में हल्दी की रस्में हुईं, जिनका दृश्य मानो झील के पानी पर तैरती सुनहरी रोशनी की तरह फैला रहा। इसके बाद सिटी पैलेस में बॉलीवुड नाइट आयोजित हुई, जहां मशहूर कलाकारों ने मंच पर आकर ऐसी परफॉर्मेंस दी कि हवेलियों की गूंज देर रात तक सुनाई देती रही।

अब सभी की निगाहें रविवार पर हैं, जब जग मंदिर पैलेस में नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू सात फेरे लेंगे। जग मंदिर की झील के बीच स्थित लोकेशन और उसकी रोशनियों के बीच शादी का दृश्य ऐसा बनने वाला है, जिसे मेहमान शायद ही कभी भूल पाएंगे। बताया जा रहा है कि हॉलीवुड कलाकार भी कई कार्यक्रमों में परफॉर्म करेंगे, जिससे यह शादी वैश्विक स्तर पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है।

उदयपुर ने कई शाही शादियां देखी हैं, लेकिन आमेर से आए इस विशेष हाथी, अंतरराष्ट्रीय मेहमानों, सितारों की परफॉर्मेंस और महलों की अनोखी रोशनी ने इस शादी को एक अलग ही दुनिया में पहुँचा दिया है—एक ऐसी दुनिया जहां परंपरा, वैभव और आधुनिकता एक साथ मिलकर इतिहास रचते हैं।

विदेश भेजने के हवाले से 28 लाख की ठगी का नेटवर्क बेनकाब शिमला में युवती बनी शातिरों का शिकार, पुलिस जांच में जुड़े सवाल

(जीएनएस)। शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर विदेश भेजने के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने कानों-कान खबर फैलते ही समाज में बेचैनी और सचेत रहने की चेतावनी जगा दी है। गुजरात निवासी एक युवती, जो वर्तमान में शिमला स्थित एसएसबी मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रही है, ने बालूगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि ‘ईगल एडवाइजर’ के नाम से सक्रिय राधिका कुमारी और इंद्रजीत ग्रेवाल ने उसे और उसकी बहन को विदेश भेजने का भरोसा दिलाकर कुल मिलाकर करीब 28 लाख रुपये वसूल लिए। रकम वसूल करने के बाद आरोपियों ने सम्पर्क तोड़ लिया और तब जाकर पीड़िता को इस ठगी का एहसास हुआ।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल जांच शुरू कर दी है। बालूगंज थाना ने आईपीसी की धारा 420 (ठगी), 120-बी (साज़िश) और 506 (धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए एएसआई अश्वनी कुमार को मामले की जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारी मामले की गहनता से पड़ताल कर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि आरोपितों ने वीज़ा, टिकटिंग या अन्य कागजी प्रक्रियाओं का मुद्दा बनाकर किस तरह पीड़िता को भरोसे में लिया। प्रारम्भिक रिपोर्ट में यह भी देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या आरोपित किसी बड़े संगठित गिरोह से जुड़े हैं और क्या इनकी इसी तरह की

विधियों से अन्य शिकार भी बने हैं।

पीड़िता की शिकायत और दिए गए दस्तावेजों की पड़ताल से पुलिस को शुरुआती सुराग मिले हैं, पर ठगी की सटीक रूपरेखा और पैसों के लेन-देन का पूरा हिसाब पता लगाने की चुनौती अभी बरक़रार है। जांच अधिकारी बताते हैं कि ऐसे मामलों में धोखाधड़ी के पैटर्न अक्सर एक जैसा होता है—प्रलोभन देने के लिए पहले भरोसा बनाया जाता है, फिर वीज़ा फीस, प्रोसेसिंग चार्ज, ईएमआई या एजेंसी फीस के रूप में लगातार छोटे-छोटे किश्तों में रकम वसूली जाती है और आखिरकार जब पीड़ित का एविडेंस कम पड़ता है तो आरोपित संपर्क काट देते हैं। पुलिस फिलहाल बैंक ट्रांज़ैक्शन, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और एजेंसी द्वारा दिए गए कागजातों की सत्यता की जाँच कर रही है।

स्थानीय व्यापारियों और प्रशिक्षण संस्थानों में इस घटना ने खलबली मचा दी है। एसएसबी मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर के प्रशासन ने भी कहा है कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है और वे पुलिस से पूरा सहयोग कर रहे हैं। केंद्र के अधिकारियों ने प्रशिक्षुओं को सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की वित्तीय लेन-देन से पहले संबंधित एजेंट की वैधता, रजिस्ट्रेशन और वास्तविक प्रमाणपत्रों की जाँच करने की सलाह दी है। कई बार प्रशिक्षण, प्लेसमेंट या विदेश में रोजगार के नाम पर युवाओं को विकसित प्रक्रियाओं में फंसा दिया जाता है; इसीलिए संस्थागत वेरिफ़िकेशन और आधिकारिक दस्तावेज़ों की पड़ताल आवश्यक बताई जा रही है।

शहर में हाल के दिनों में विदेश भेजने के नाम पर ठगी के कई प्रकरण उभरने की बात भी स्थानीय पुलिस और नागरिकों ने स्वीकार की है। इसी कारण से ठगी का यह नया मामला नागरिकों के बीच दहशत फैलाने के साथ-साथ प्रशासन के लिए भी अलार्म की तरह काम कर रहा है। पुलिस अधिकारी इस बात पर बल दे रहे हैं कि सामान्य नागरिक किसी अज्ञात या अनधिकृत एजेंट को अपनी निजी जानकारी, बैंक विवरण अथवा अग्रिम भुगतान न दें। यदि कोई एजेंट अचानक आकर्षक ऑफर, त्वरित वीज़ा, या सस्ते पैकेज का लालच दे, तो पहले उससे संबंधित सभी आधिकारिक रिकॉर्ड मांगें और कार्यालय की उपस्थिति, शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध संपर्क तथा अन्य ग्राहकों के रिव्यू चेक करें।

कानूनी तौर पर भी इस तरह की ठगी के लिए सज़ाएँ कड़ी हैं, परन्तु पीड़ितों को अपने पैसे वापस दिलाना और वास्तविक अनुचित लेन-देन को साबित कराना अक्सर कठिनाइयों से भरा होता है। इसलिए पुलिस का ध्यान डिजिटल फॉरेंसिक, बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से पैसों के फ्लो का सुराग, और आरोपितों के संपर्कों तक पहुंचने पर टिका हुआ है। एएसआई अश्वनी कुमार ने बताया कि टीम तमाम समन्वित प्रयास कर रही है—सीसीटीवी फुटेज, बैंक पासबुक और मोबाइल रिकार्ड्स के माध्यम से आरोपितों के वास्तविक ठिकानों तक पहुंचने का प्रयास तेज किया गया है।

अमेठी में ‘रन फॉर यूनिटी’ का जोश, अपर्णा यादव का बड़ा राजनीतिक बयान-2027 में भी एनडीए की प्रचंड वापसी तय

(जीएनएस)। अमेठी। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर अमेठी में आयोजित “रन फॉर यूनिटी” कार्यक्रम रविवार को एक बड़े जनसमूह की ऊर्जा और उत्साह के साथ इतिहास बन गया। सुबह से ही शहर के कोने-कोने से लोग रामलीला मैदान की ओर उमड़ पड़े थे, जहां से पदयात्रा की शुरुआत होनी थी। स्कूली बच्चों की कतारें, हाथों में तिरंगों की लहराती धारियां, बुजुर्गों की धीमी लेकिन दृढ़ चाल और युवा वर्ग के जोशीले नारों ने पूरे माहौल को एकता की भावना से सराबोर कर दिया। यही वह मंच था जहां उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने एक ऐसा राजनीतिक संकेत दिया जिसने आने वाले चुनावी मौसम की हवा पहले ही गर्म कर दी है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर्णा यादव ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बेहद आत्मविश्वासपूर्ण अंदाज में कहा कि भाजपा और एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में एनडीए ने मजबूत प्रदर्शन किया है, उसी प्रकार पूरे देश में यह राजनीतिक ध्रुवीकरण और जनसमर्थन

कायम रहेगा। उनके शब्दों में यह स्पष्ट महसूस किया जा सकता था कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक विस्तार, विकास एजेंडा और मतदाता विश्वास के आधार पर एक बार फिर बड़े बहुमत से सत्ता में लौटने की तैयारी में है।

अपर्णा ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के मंत्र का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत की विकास यात्रा आज एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार और गरीबों के उत्थान के लिए नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर अभियान का उल्लेख किया, जिसमें मृत मतदाताओं, रोहिंग्या नागरिकों और फर्जी वोटों को मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने इसे चुनाव प्रक्रिया के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम बताया।

कार्यक्रम की शुरुआत रामलीला मैदान से हुई, जहां हजारों की संख्या में शामिल लोग उत्साह से भरे नजर आए। जैसे ही पदयात्रा आगे बढ़ी, आमजन के साथ-साथ स्थानीय सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कदम से कदम मिलाया। पदयात्रा गांधी चौक से होते हुए अंबेडकर तिराहे तक पहुंची, जहां राष्ट्रभक्ति गीतों की गूंज पूरे वातावरण में फैल गई। कई स्थानों पर लोगों ने फूलों की बौछार कर स्वागत किया, लेकिन जेसीबी मशीनों से की गई पुष्पवर्षा ने लोगों का ध्यान सबसे अधिक खींचा। यह दृश्य एक उत्सव जैसा था, जहां एकता का संदेश और राजनीतिक ऊर्जा दोनों साथ-साथ दिखाई दे रहे थे।

स्कूली बच्चों की भागीदारी विशेष रूप से मन मोह लेने वाली रही। उनकी आवाज़ में जो देशभक्ति और गर्व का स्वर था, वह बताता था कि नई पीढ़ी एकता दिवस जैसे आयोजनों को केवल उत्सव की तरह नहीं देखती, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और नागरिक जिम्मेदारी के तौर पर भी स्वीकार करती है। तिरंगा लहराते हुए बच्चों ने जिस तरह पूरे मार्ग को सजीव बना दिया, वह भीड़ के उत्साह को और बढ़ाता चला गया।

पदयात्रा के समापन पर रामलीला मैदान में आयोजित सभा में सभी मुख्य अतिथियों का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष ने अपर्णा यादव को पुष्पगुच्छ भेंट किया, जबकि भाजपा नेता शरद शंकर मिश्र ने सरदार पटेल की प्रतिमा भेंट कर उनका सम्मान किया। सभास्थल पर लोगों का उत्साह ऐसा था मानो एक राजनीतिक रैली की बजाय किसी ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा हों।

अपर्णा के भाषण ने न केवल राजनीतिक विमर्श को नई दिशा दी, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा की रणनीति आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कितनी सजग और व्यापक रूप से तैयार है। अमेठी, जो कभी राजनीतिक उठापटक का केंद्र रहा है, वहां इस प्रकार का आयोजन और बयान यह संकेत दे रहे हैं कि 2027 की जंग शुरू होने से पहले ही सियासी हवा का रुख तय किया जाने लगा है।

अमेठी में इस एकता और उत्साह से भरे आयोजन ने यह भी दिखाया कि जनता विकास, स्थिरता और राष्ट्रीय एकजुटता को कितनी गंभीरता से लेकर चल रही है।

पाकुड़ में मेले की आड़ में रची गई हैवानियत की साजिश: प्रेम का भरोसा तोड़कर सुनसान जगह में गैंगरेप, पूरे इलाके में उबाल

(जीएनएस)। झारखंड के पाकुड़ जिले में विश्वास, प्रेम और मासूमियत को कुचल देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। महेशपुर थाना क्षेत्र में हुई यह वारदात सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि उस भरोसे की हत्या है जो एक किशोरी ने अपने प्रेमी पर किया था। यह कहानी किसी मेला, रौशनी और हँसी के बीच शुरू हुई, लेकिन अंधेरे, सन्नाटे और बेचैनी में खत्म हो गई।

एक नाबालिग प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को बड़ी मासूमियत से यह कहकर बुलाया कि वह उसे मेला दिखाने ले जाएगा। लड़की को क्या पता था कि जिस हाथ को वह सहारा मानती है, वही हाथ उसे सबसे गहरे अंधेरे में धकेल देगा।

मेला खत्म हुआ तो प्रेमी ने उसे यह कहकर अलग रास्ते की ओर मोड़ दिया कि वह थोड़ी देर शांति से बात करना चाहता है। लेकिन जैसे-जैसे रास्ता वीरान होता गया, किशोरी का अनजाना डर बढ़ता गया — वह डर, जो अक्सर किसी अनहोनी से ठीक पहले दिल में घर कर जाता है।

सुनसान जगह पहुंचते ही मामला बदल गया। वह लड़का, जिससे वह प्यार जताती रही, अचानक दरिंदा बन गया। उसने रिश्ते का सम्मान नहीं किया, प्रेमिका की पुकार नहीं सुनी — सिर्फ अपनी हवस के आगे झुक गया। और जब पीड़िता चीखती रही, रोकने की कोशिश करती रही, तब उसने अपने तीन अन्य दोस्तों को भी वहीं बुला लिया।

जो जगह दो लोगों के मिलने की थी, वह अचानक चार हैवानों का अड्डा बन गई और बारी-बारी से चारों ने किशोरी की अस्मिता को तार-तार कर दिया।

उस क्षण में लड़की की हर पुकार, हर विनती, हर दुआ जैसे हवा में खो गई। लेकिन वह टूटने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। मौका मिलते ही उसने मोबाइल के जरिए अपने परिवार को संदेश भेज दिया— वही पल उसके बचाव की वजह बन गया।

सूचना मिलते ही महेशपुर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। चारों आरोपी भागने की कोशिश में थे, मगर कानून के हाथों से बच नहीं सके।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तीन नाबालिग हैं, जिनमें किशोरी का प्रेमी भी शामिल है। इन तीनों को बाल सुधार गृह भेजा गया है, जबकि चौथे वयस्क आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

घटना के बाद से पूरे इलाके में गुस्सा है, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और परिजन सदमे में हैं कि जिस लड़के पर उनकी बेटी ने भरोसा किया, वही उसका सबसे बड़ा गुनहगार निकला।

यह पहली बार नहीं है कि ऐसी घटना राज्य को झकझोर रही हो। कुछ ही समय पहले रांची के रातू थाना क्षेत्र में भी एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था— वहां नौ दरिंदों ने एक लड़की को जतरा मेला देखकर लौटते वक्त हवस का शिकार बनाया था। उस मामले में भी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर पांच आरोपियों को पकड़ लिया था।

इन घटनाओं ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है — क्या समाज में बढ़ती संवेदनहीनता, मोबाइल और सोशल मीडिया पर रिश्तों का हल्का होता अर्थ, और बच्चों में बढ़ता अपराध का दायरा हमारी आने वाली पीढ़ियों को और अधिक खतरनाक मोड़ पर ला रहा है?

पाकुड़ की यह घटना सिर्फ एक पुलिस केस नहीं, बल्कि चेतावनी है कि भरोसा जब टूटा है, तो सबसे ज्यादा दर्द समाज को होना चाहिए। क्योंकि मेले की चमक के पीछे छिपी यह साज़िश दिखाती है कि इंसानियत का अंधेरा चेहरा किसी भी समय, किसी भी जगह उभर सकता है — और इसके खिलाफ केवल कानून ही नहीं, समाज को भी खड़ा होना होगा।

देवघर में AK–47 का बर्स्ट मोड अचानक सक्रिय, ताबड़तोड़ गोलियों ने छीन ली जवान की जान: प्रशिक्षण ग्राउंड पर गूँजी दहशत और पूरी रात चली जांच

(जीएनएस)। झारखंड के देवघर जिले में हुई एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना ने पूरे पुलिस महकमे को स्तब्ध कर दिया है। मोहनपुर थाना क्षेत्र में झारखंड सशस्त्र पुलिस के हवलदार शिवपूजन पाल की मौत उस समय हो गई, जब उनकी ही सर्विस राइफल AK-47 अचानक बर्स्ट मोड में चली गई और लगातार निकली गोलियों ने उनकी गर्दन को चीर डाला।

जिस जगह प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन और सुरक्षा सर्वोच्च होती है, उसी जगह अचानक गूँजी गोलियों की आवाज़ ने जवानों और अधिकारियों को कुछ क्षणों के लिए सुन्न कर दिया।

यह हादसा उस समय हुआ, जब हवलदार शिवपूजन पाल अपनी AK-47 राइफल की शूटिंग रिंग (चेंबर) को चार्ज दे रहे थे। प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई, राइफल ने एक नहीं, बल्कि लगातार कई गोलियां उगल दीं— मानो बटन दबते ही हथियार ने नियंत्रण खो दिया हो।

गोलियां सीधे उनकी गर्दन में जाकर लगीं और कुछ ही सेकंड में उन्होंने दम तोड़ दिया। साथी जवान जब तक दौड़कर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

इस शूटिंग रेंज जैसी जगह पर इस प्रकार की अनियंत्रित फायरिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या राइफल में किसी तकनीकी खराबी ने बर्स्ट मोड को सक्रिय कर दिया? क्या सेफ्टी-कंट्रोल में कोई चूक हुई? या फिर यह मानव-त्रुटि थी, जो सामान्य अभ्यास को मौत की घटना में बदल गई? घटना की गंभीरता को देखते हुए देवघर पुलिस और उच्च अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई जारी है। राइफल को सील कर दिया गया है और उसकी मैकेनिकल जांच भी शुरू कर दी गई है।

फॉरेंसिक टीम मौके पर घंटों तक जांच करती रही। उन्होंने जमीन पर बिखरी गोलियों के खोल, राइफल की पोज़िशन, सेफ्टी लीवर की स्थिति, ट्रिगर सिस्टम और फायरिंग रेंज के एंगल तक हर पहलू का निरीक्षण किया।

बेगूसराय में मुठभेड़ के बाद कुख्यात शिवदत्त राय गिरफ्तार, मकान के अंदर चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश — एक पूरे नेटवर्क के उजागर होने की दास्तान

(जीएनएस)। पटना। बिहार की धरती एक बार फिर हथियारों और अपराध की दुनिया में सक्रिय एक खतरनाक नेटवर्क के भंडाफोड़ की गवाही दे रही है। बिहार एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार देर रात साहेबपुर कमाल में एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जिसने पूरे जिले में खलबली मचा दी। कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह वही नाम है जिस पर पहले से कई संगीन मामले दर्ज हैं और जो लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बचता रहा था।

लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया—और शायद उसने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि उसके ठिकाने से एक

बड़े अवैध हथियार तंत्र का खुलासा होने जा रहा है।

मुठभेड़ की रात तेज़ हवा, अंधेरा और अचानक सायरनों की आवाज़ ने पूरे इलाके को हिला दिया। पुलिस की टीम जैसे ही साहेबपुर कमाल के उस घर के पास पहुंची जहां शिवदत्त के छिपे होने की खबर थी, भीतर मौजूद अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पल भर में पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया। जवाबी कार्रवाई हुई और कुछ ही मिनटों के भीतर गोलियों की आवाज़ थम गई। शिवदत्त राय घायल अवस्था में पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया—और यहीं से शुरू हुई असली कहानी।

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उसकी निशानदेही पर अमित कुमार गुप्ता के मकान पर छापा मारा, तो सामने जो दृश्य आया, वह किसी अपराध पर आधारित फिल्म जैसा था। बंद दरवाज़े खुलते ही अधिकारियों के सामने एक सक्रिय मिनी गन फैक्ट्री दिखाई दी—बंदूकें, मशीनें, हथियार बनाने के सांचे, अधबने पिस्टल, कारतूस, नकदी सब कुछ जैसे किसी बेहद संगठित अपराधी गिरोह का चेहरा उजागर कर रहे थे। पुलिस की बरामदगी इतनी बड़ी थी कि अधिकारी भी हैरान रह गए। सात देसी पिस्टल, एक अधनिर्मित पिस्टल, सात मैगजीन, 3,70,000 नकद, 970 बोतल अवैध कफ सिरप, कार्बाइन, दर्जनों कारतूस और हथियार बनाने वाले उपकरण—यह बताने के लिए काफी था कि यह मामला सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक बड़े और खतरनाक नेटवर्क के जड़ से उखाड़ने का कदम है। अवैध कफ सिरप की 970 बोतलें यह संकेत देती हैं कि यहां सिर्फ हथियारों का धंधा नहीं, बल्कि नशे के कारोबार की भी काली रेखा जुड़ी हुई थी। इन नेटवर्कों से जुड़ी गाड़ियां, बाहरी संपर्क और सप्लाई चेन की जानकारी जुटाने में पुलिस अब जुट गई है।